भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम 21 को

लैपटॉप खरीदने मेधावी छात्रों के खातों में 224 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे मोहन

सच प्रतिनिधि II भोपाल।

सरकारी स्कूलों में 80 प्रतिशत से अधिक छात्र-छात्राओं को लैपटॉप मिलना तय हो गया है। मोहन सरकार ने इसके लिए तारीख की घोषणा भी कर दी है। इसके अनुसार सरकारी स्कूलों में पिछले साल 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से लैपटॉप खरीदने के लिए 21 फरवरी को राशि जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राजधानी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों के खातों में 224 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 21 फरवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 89,700 विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप के लिए राशि भेजी जाएगी। प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। हालांकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिन मेधावी छात्रों को बुलाया गया है, उनके खातों में लैपटॉप की राशि पहले ही जारी कर दी गई है। जिससे वो कार्यक्रम वाले दिन लैपटाप लेकर पहुंचे। यही लैपटॉप सीएम छात्रों को सांकेतिक रूप से वितरित करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छात्रों के खातों में सीधे राशि भेजने से वो अपनी पसंद का लैपटॉप खरीद सकते हैं। साथ ही इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती है। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक लाने वालों को फ्री लैपटॉप देने की योजना साल 2009-10 में शुरू की गई थी। तब 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वालों की संख्या 20 से 25 हजार के बीच होती थी। लेकिन इन 14 सालों में 75 प्रतिशत से अधिक नंबर वाले मेधावी विद्यार्थियों की संख्या 90 हजार तक पहुंच गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के कारण ही प्रदेश में ऐसे मेधावी विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है।

बीते 5 फरवरी को सीएम डॉ मोहन यादव ने राजधानी के कुशाभाउ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सरकारी स्कूलों में टॉप करने वाले 7800 विद्यार्थियों के खातों में स्कूटी खरीदने के लिए राशि खातों में हस्तांतरित की थी। इनमें बच्चे अपनी इच्छानुसार ई-स्कूटी या पेट्रोल स्कूटी का चयन कर सकते थे। सरकार ने ई-स्कूटी खरीदने वाले बच्चों को 1.।10 लाख रुपये और स्कूटी खरीदने वाले बच्चों के खातों में 90 हजार रुपये हस्तांतरित किए थे। अधिकारियों ने बताया कि साल 2023-24 के टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण में करीब 80 करोड़ रुपये खर्च हुए।

सीएम आज जबलपुर में करेंगे

हाईटेक गौशाला का भूमिपूजन

जबलपुर। प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के वार्ड नंबर 79 में 10 करोड़ की लागत से नगर निगम हाईटेक गौ-शाला का निर्माण कर रहा है। इसका भूमिपूजन करने के लिए आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर आएंगे। गौ-शाला करीब 53 एकड़ में आकार लेगी। इस गौ-शाला के बनने के बाद सड़क पर घूम रहे गोवंश को आश्रय मिलेगा। भूमिपूजन के दौरान सीएम के साथ राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, कलेक्टर दीपक सक्सेना, नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव, महापौर जगत बहादुर अन्नू सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद रहेंगे। गौ-शाला की क्षमता 10 हजार गौ-वंश की होगी। वर्तमान में यहां पर तीन हजार गौ-वंश पहले से ही मौजूद हैं। गौ-शाला का कुल रकबा 95 एकड़ का है। भविष्य में यहां पर बायो गैस और गौमूत्र प्लांट लगाने की भी योजना है। गौ-शाला का भूमिपूजन करने के लिए मुख्यमंत्री दोपहर दो बजे हेलिकॉप्टर से उमरिया गांव पहुंचेगें।

यहां पर एक विशाल मंच बनाया गया है। मंच पर नेताओं के अलावा साधु-संत भी बैठेंगे। उमरिया के कार्यक्रम के बाद सीएम मोहन यादव हेलिकॉप्टर से गोकलपुर पहुंचेंगे, जहां वो रांझी में बने खेल परिसर का लोकार्पण करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव गोकलपुर से सड़क के रास्ते शहीद स्मारक जाएंगे। जहां पर केंद्रीय बजट पर प्रबुद्धजनों के साथ परिचर्चा में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले होंगे टेंडर

लेक व्यू अशोका, हलाली रिट्रीट समेत 10 प्रॉपर्टी को निजी हाथों में देगी सरकार

सच प्रतिनिधि II भोपाल।

भोपाल के लेक व्यू अशोका, हलाली रिट्रीट समेत 10 से ज्यादा होटल, रिसोर्ट, वेलनेस सेंटर या गोल्फ ग्राउंड को सरकार प्राइवेट हाथों में सौंपने कर रही है। इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर चलाया जाएगा। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) में इन प्रॉपर्टी को प्रजेंटेशन के जरिए इन्वेस्टर्स को सरकार दिखाएगी।

सबसे बड़ी प्रॉपर्टी भोपाल की लेक व्यू अशोका रेजीडेंसी है। नई दिल्ली में प्रजेंटेशन देने के बाद अब इस होटल का प्रजेंटेशन होटल या रिसोर्ट सेक्टर से जुड़े उद्योगपतियों को दिखाया जाएगा। ताकि, वे इन्वेस्ट करें। लेक व्यू अशोका होटल के संबंध में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सीएम डॉ. मोहन यादव और मंत्रियों के बीच मंथन हुआ। साथ ही, मध्यप्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अपनी उन प्रॉपर्टी का प्रजेंटेशन करने का निर्णय लिया है, जिन्हें पीपीटी मॉडल पर देना है। लेक व्यू अशोका समेत कुछ प्रॉपर्टी के लिए पहले भी पहल हो चुकी है, लेकिन सही ऑफर नहीं मिलने के कारण इसे टाला जा रहा था। अब इन सभी यूनिट्स को जीआईएस में इन्वेस्टर्स को दिखाई जाएगी।

जीआईएस से पहले टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी

करीब चार महीने पहले टेंडर की शर्तें तैयार करके वित विभाग को मंजूरी के लिए भेजी गई थी। अब इसे कैबिनेट में रखा गया है। अफसरों के अनुसार, जीआईएस से पहले टेंडर प्रि या शुरू होगी। ताकि, होटल-रिसोर्ट सेक्टर से जुड़े उद्योगपति इन्वेस्ट कर सकें। दूसरी ओर, 3 फरवरी को नई दिल्ली में मध्यप्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रजेंटेशन भी दिखा चुका है। इसमें 25 से अधिक उद्योगपति मौजूद थे।

नए सिरे से बनेगी होटल

अफसरों के अनुसार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर देने के बाद संबंधित एजेंसी ही होटल को नए सिरे से बनाएगी। लीज केवल उन्हीं फर्मों, एजेंसियों या होटल संचालन से जुड़ी कंपनियों को दी जाएगी, जो पर्यटन विभाग को हर साल करीब 4 करोड़ रुपए की फिक्स राशि देंगी। साथ ही, मुनाफे में भी ज्यादा हिस्सा दे सके, इसका ध्यान रखा जाएगा। मुनाफे की हिस्सेदारी का प्रतिशत भी तय किया जाएगा और इसे टेंडर की शर्तों में शामिल किया जाएगा।

इन यूनिट्स में निवेश का ऑफर

लेक व्यू अशोका, सांची का गेट वे रिट्रीट होटल समेत एक दर्जन से अधिक यूनिट्स में निवेश का ऑफर दिया जाएगा। ये यूनिट्स पीपीपी मोड, मैनेजमेंट कॉन्टैक्ट या लीज पर 60 से 90 साल के लिए दी जाएगी। इन सभी यूनिट्स का संचालन मप्र राज्य पर्यटन विकास निगम कर रहा है और कई यूनिट फायदे में भी है।

खजुराहो कन्वेंशन सेंटरः छतरपुर जिले के खजुराहो में बना राजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर को भी जीआईएस में रखा जाएगा। प्रदेश के 10 पर्यटन स्थलों पर संचालित सभी साउंड एंड लाइट शो को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की गई है। इनमें ओरछा, खजुराहो, सांची, पचमढ़ी, चंदेरी, बुरहानपुर, इंदौर और ओंकारेश्वर शामिल है। इसके अलावा महेश्वर और उज्जैन में भी अगले माह साउंड एवं लाइट शो शुरू किए जाएंगे।

शहडोल जिले में बाणसागर डैम के बैक वाटर क्षेत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा आइलैंड रिसॉर्ट सरसी का भी विस्तार होगा। इसके लिए भी निजी निवेशकों को ऑफर दिया जाएगा। 23 एकड़ में फैले इस रिसॉर्ट की दो महीने पहले की शुरुआत हुई है। जीआईएस में टूरिज्म कॉर्पोरेशन इन्वेस्टर्स को कुल 25 लोकेशन दिखाएगा। ये सभी लोकेशन होटल, रिसॉर्ट, वेलनेस सेंटर और टूरिज्म एक्टिविटी से जुड़ी हैं। इनमें कुल 62 करोड़ रुपए का निवेश हो सकेगा। यह प्रॉपर्टी जबलपुर, मंदसौर, धार, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, नीमच, बैतूल, रायसेन, बुरहानपुर, शाजापुर, शहडोल, विदिशा और अलीराजपुर जिलों में है।

अफसरों ने बताया, प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर हैं, जहां टूरिज्म एक्टिविटी आसानी से हो सकती है। मंदसौर के गांधीसागर में तो हरियाली के बीचोंबीच प्रॉपर्टी है। वहीं, धार के हेमाबर्डी में फिक्स्ड टेंटिंग यूनिट यानी, टेंट सिटी बनाई जा सकती है। अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा, बैतूल के भैंसदेही, मंदसौर के मल्हारगढ़, जबलपुर के नन्हाखेड़ा जैसी लोकेशन भी हैं।

नेता, अफसरों से हो सकती है पूछताछ

सौरभ शर्मा के ठिकानों से मिले ट्रांसफर पोस्टिंग के दस्तावेजों की जांच शुरू

सच प्रतिनिधि II भोपाल।

आरटीओ के पूर्व करोड़पति कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों से मिले ट्रांसफर-पोस्टिंग के दस्तावेजों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू कर दी है। इसमें ईडी कुछ नेताओं और अफसरों से भी पूछताछ कर सकती है। इसके लिए दिल्ली मुख्यालय से मशविरा मांगा है। उधर, भोपाल में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर तुषार श्रीवास्तव का दिल्ली तबादला हो गया है। विभागीय सूत्रों की दलील है कि ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। श्रीवास्तव के साथ 53 अफसरों के तबादले किए गए हैं। ईडी ने 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नकद का लिंक तो डॉक्यूमेंट कर दिया है, लेकिन सौरभ से ये नहीं उगलवा पाई है कि ये किसका है? अब तक की जांच में ईडी ने जो प्रॉपर्टी सीज की हैं, उसका हिसाब देने के लिए सौरभ और उसके रिश्तेदारों-दोस्तों को 15 मार्च की डेडलाइन दी है।

हरे रंग की डायरी में मिले हिसाब की कड़ी जोड़ी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सौरभ के घर से हरे रंग की एक डायरी मिली थी। इस डायरी में 66 पन्ने हैं। इसमें टीएम और टीसी जैसे कोड वर्ड के आगे नंबर लिखे हैं। जांच एजेंसी को संदेह है कि ये नंबर इन लोगों को दिए गए रुपयों के हैं।

एजेंसी का संदेह इसलिए भी पुख्ता है, क्योंकि सौरभ के ठिकानों से परिवहन विभाग के ट्रांसफर-पोस्टिंग के दस्तावेज और सरकारी नोटशीट मिली है। साथ ही टोल नाकों के रसीद-कट्?टे भी मिले हैं। ये सबूत भी मिले हैं कि सौरभ नौकरी से इस्तीफा देने के बाद भी परिवहन विभाग में सक्रिय था। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने सौरभ से पूछताछ में इसे वेरिफाई भी कर लिया है। साथ ही शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर से भी सारे सवाल पूछे हैं। अब सिर्फ ये वेरिफाई होना बाकी है कि उनकी प्रॉपर्टी के लिए भुगतान किसने किया था?

ईडी ने 94 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की खरीदी का सौरभ, उसकी मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या, साले रोहित तिवारी, सुलभा तिवारी, चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल और शरद की मां कृष्णा जायसवाल से जवाब मांगा है। ईडी के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह कहते हैं- जांच एजेंसी को छापों में जो भी संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, उन्हें वो रिकॉर्ड पर लेती है। इसके लिंक जोड़ने के बाद ही वो उस दिशा में जांच आगे बढ़ाती है। ईडी को जांच में जिस संपत्ति के भ्रष्टाचार से लिंक होने के प्रमाण मिलते हैं, वो उसे सीज करती है।

कल पहली बार भोपाल आएंगे हरीश चौधरी

कांग्रेस के नए प्रभारी से पटवारी और सिंघार ने की अलग अलग मुलाकात

भोपाल। मप्र में कांग्रेस को एक तरफ जहां चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी टिक नहीं पा रहे हैं। तीन सालों में चार प्रभारी बदले जा चुके हैं। तीन दिन पहले भंवर जितेन्द्र सिंह को हटाकर राजस्थान के बायतू से विधायक हरीश चौधरी को मप्र का प्रभारी बनाया गया है।

कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी कल पहली बार भोपाल आएंगे। वे पीसीसी में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक लेकर मेल-मुलाकात करेंगे।

मप्र कांग्रेस के निवर्तमान प्रभारी भंवर जितेन्द्र सिंह विधानसभा चुनाव 2023 में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। विधानसभा की 230 सीटों में से कांग्रेस को मात्र 66 सीटें मिलीं थीं। 163 सीटें बीजेपी और एक बीएपी ने जीती थी।

विधानसभा चुनाव के दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रभारी थे। चुनाव में हार के बाद सुरजेवाला को हटाकर जितेन्द्र को प्रभारी बनाया गया था। लेकिन, लोकसभा चुनाव में मप्र की सभी 29 सीटों पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा।

विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान रणदीप सुरजेवाला प्रभारी और भंवर जितेन्द्र सिंह स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। सप्तागिरी उल्का और अजय लल्लू स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य थे। भंवर जितेन्द्र सिंह के खिलाफ लगातार कांग्रेस आलाकमान तक ये शिकायतें पहुंच रहीं थीं कि वे गुटीय राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछेक लोगों के इशारे पर सारे फैसले हो रहे हैं। इसके बाद भंवर जितेन्द्र सिंह को हटाकर हरीश चौधरी को कमान दी गई है।

एमपी में नहीं टिक पा रहे कांग्रेस के प्रभारी- मोहन प्रकाश की जगह सितंबर 2017 में दीपक बावरिया को प्रदेश प्रभारी बनाया गया था। अप्रैल 2020 में दीपक बावरिया ने एमपी के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मई 2020 में मुकुल वासनिक एमपी के प्रभारी बनाए गए थे।

सितंबर 2022 में मुकुल की जगह जेपी अग्रवाल को प्रभारी नियुक्त किया गया था। अगस्त 2023 में जेपी अग्रवाल की जगह रणदीप सिंह सुरजेवाला को एमपी का प्रभार सौंपा गया था। दिसंबर 2023 में सुरजेवाला की जगह भंवर जितेन्द्र सिंह को इंचार्ज नियुक्त किया गया था। जितेन्द्र सिंह की जगह अब हरीश चौधरी को कमान सौंपी गई है।

भोपाल-जबलपुर के बीच नए हाई-स्पीड फोरलेन का सर्वे शुरू

सच प्रतिनिधि II भोपाल।

मध्यप्रदेश में सड़कों के विस्तार और उनके सुधार में तेजी से काम हो रहा है। नए सरपट हाईवे भी बनाए जा रहे हैं और अब मध्यप्रदेश के दो प्रमुख शहर भोपाल और जबलपुर के बीच नया हाई-स्पीड फोरलेन बनाया जाएगा। भोपाल-जबलपुर के बीच बनने वाले नए हाई स्पीड फोरलेन को केन्द्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने के लिए सर्वे काम शुरू हो गया है। बीते दिनों भोपाल में इंडियन रोड कांफ्रेंस के दौरान ये बात उठी थी कि भोपाल-जबलपुर के बीच नया हाई-स्पीड फोरलन बनाया जाए। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी से इसे लेकर चर्चा की थी जिसके बाद इसे केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबलपुर से भोपाल की यात्रा को तेज और सुगम बनाने के लिए नए शॉर्टकट रूट की तलाश की जाएगी। भोपाल-जबलपुर नए हाई स्पीड फोरलेन के लिए सर्वे होने के बाद डीपीआर तैयार कर इसके काम को आगे बढ़ाया जाएगा। भोपाल-जबलपुर नए हाई स्पीड फोरलेन बनने से न केवल दोनों शहरो के बीच का सफर कम समय में पूरा किया जा सकेगा बल्कि इसके जरिए व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

पांच जिलों की कनेक्टिविटी का बन रहा प्लान

ग्रेटर भोपाल के लिए पहला कदम उठाया जा रहा है। भोपाल से जुड़े विदिशा, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम व राजगढ़ से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पीडब्ल्यूडी ने योजना बनाना शुरू कर दी है। अगले एक माह में भोपाल से जुड़े पांच जिलों से रोड नेटवर्क को लेकर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी इसके लिए कंसल्टेंट तय कर रही है। टीएंडसीपी की ओर से पीडब्ल्यूडी से इसे लेकर जानकारी मांगी गई है। गौरतलब है कि हाल में आंबेडकर ब्रिज लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने वृहद राजधानी की बात कही थी। इसके बाद से ही इस पर काम चल रहा था। अब जमीन पर इसे उतारने की योजना तय की जा रही है। ग्रेटर भोपाल के प्लान के लिए भोपाल का मास्टर प्लान रोका जाएगा। इसके लिए टीएंडसीपी के अफसरों को शासन की ओर से कहा गया है। अब भोपाल समेत आसपास के पांच जिलों का पूरा क्लस्टर बनाकर विकास की योजना तय होगी। इसमें सीहोर भोपाल से लेकर भोपाल नरसिंहगढ़, ब्यावरा से राजगढ़, भोपाल से नर्मदापुरम, भोपाल से विदिशा व भोपाल से रायसेन तक की अलग प्लानिंग होगी। अभी भोपाल व सीहोर अलग-अलग प्लान बनाते हैं। सीहोर व भोपाल में बड़ा तालाब व इसका कैचमेंट आता है। अलग- अलग होने से संरक्षण पर काम आधा अधूरा होता है, अब पूरा होगा। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र भोपाल के पास है, लेकिन इसके रायसेन जिले में होने की वजह से भोपाल से इसे लेकर कोई प्लानिंग नहीं की जा सकती। भोपाल के साथ ये वैश्विक नक्शे में भी नजर नहीं आता। वृहद राजधानी में भोपाल के साथ इसके लिए प्लानिंग हो सकती है। भोपाल से लगे होने के बाद भी वैश्विक धरोहरें सांची, भीम बेटिका और अन्य पर भोपाल से काम नहीं हो सकता। अब ये जुड़कर काम करेंगे। भोपाल में मेट्रो का नेटवर्क अभी मंडीदीप तक बढ़ाया जा रहा है। आगामी समय में बड़े बजट से भोपाल के 100 किमी दायरे के बाहर भी मेट्रो की आवाजाही आसान हो जाएगी।

बजट सत्र : बेफिजूल खर्च पर सरकार की नजर

बजट में कटौती की तैयारी में मोहन सरकार

भोपाल। केंद्रीय बजट के बाद मोहन सरकार ने विभाग के वे योजनाएं जिनमें बे फिजूल पैसों का खर्च हो रहा है, उनके मैंनेजमेंट को लेकर उच्च अधिकारियों में विचार विमर्श तेज हो गया है। फोकस कमाऊ विभागों पर अधिक है। खर्चों को कम करने को लेकर भी गणित लगाया जा रहा है। अनावश्यक खर्चों में कटौती का तैयारी मोहन सरकार ने लगभग पूरी कर ली है। यह भी तय किया गया है कि जनहितैषी योजनाओं के लिए खजाना खुला रहेगा, वहीं उपयोगिता खो चुकी योजनाओं के लिए बजट नहीं देने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। इससे जो बजट बचेगा, उसे अन्य उपयोग में लिया जाएगा। 10 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार बजट पेश करेगी। यह चार लाख करोड़ तक का हो सकता है। वित्त विभाग पहले ही विभागों से प्रस्ताव मंगवा चुका है।

चालू वित्तीय वर्ष में बजट 3.65 लाख करोड़ का है। इससे ज्यादा राज्य में कर्ज है। सरकार की चिंता कर्ज का बोझ कम करने को लेकर है। इसलिए आय बढ़ाने के साधनों पर मंथन चल रहा है। कमाऊ विभागों के साथ सीएम चर्चा कर चुके हैं। आमजन का भी ध्यान रखा जा रहा है। युवा, महिला, गरीब, किसान के लिए अलग-अलग प्रावधान किए जा रहे हैं। सरकार इन वर्गों के लिए अलग-अलग मिशन भी लागू कर रही है। इस वर्ग के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पर्याह्नश्वत राज्यांश भी रखा जाएगा। उधर, वित्त विभाग ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि एक जैसी प्रकृति की योजनाओं को मिलाने पर विचार किया जाए। जिन योजनाओं के लक्ष्य पूरे हो चुके हों, उन्हें बंद करने को कहा है। इन योजनाओं के लिए वित्त बजट नहीं देगा। अंतिम निर्णय सीएम के स्तर पर लिया जाएगा।

अतिथि विद्वानों की पीएचडी अनिवार्यता पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के गेस्ट टीचर्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के लिए पीएचडी की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षक भर्ती नियम की धारा 10.4 पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि पुरानी भर्तियों पर नए नियम लागू नहीं हो सकते हैं। राज्य सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जारी नियम अतिथि शिक्षकों पर भी लागू कर दिए थे, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में यह याचिका अतिथि शिक्षक प्रियंका उपाध्याय, पुष्पा चतुर्वेदी सहित अन्य 13 लोगों ने दायर की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एक तरफ तो जो अतिथि विद्वान पहले से कार्यरत हैं, उन्हें यथावत रखा जाएगा, लेकिन फेलन आउट (जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है) अतिथि विद्वानों को बगैर पीएचडी के कंटीन्यू नहीं किया जाएगा।

कोर्ट को बताया- रेगुलर न रखना भेदभावपूर्ण- आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 2023 के दिशा-निर्देश की कंडिका 10.4 अवैध और भेदभावपूर्ण है। सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की अनिवार्यता पहले की है, इसलिए बगैर पीएचडी वाले अतिथि विद्वानों को रेगुलर न रखना न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है, बल्कि गलत भी है।

भीड़ प्रबंधन के लिए महाकाल मंदिर में 9 अधिकारी नियुक्त

उज्जैन। महाकाल मंदिर में बिगड़ती व्यवस्था और आए दिन भस्म आरती में प्रवेश को लेकर हो रहे फर्जीवाड़े और विवाद की खबरें सामने आती हैं। इसे देखते हुए आईपीएस अधिकारी को मंदिर प्रशासक बनाने के बाद अब दो डिप्टी कलेक्टर सहित दो नायब तहसीलदार और 5 अन्य अधिकारियों को महाकाल मंदिर में नियुक्त किया गया है। महाकाल मंदिर में लगी आग, दीवार गिरने, और प्रवेश के नाम पर अवैध वसूली में हुई एफआईआर के बाद द्रुस प्रथम कौशिक को मंदिर का प्रशासक बनाया गया था। कलेक्टर कार्यालय से करीब चार दिन पहले जारी ऑर्डर के बाद अब मंदिर की व्यवस्था सुधारने के लिए दो डिप्टी कलेक्टर सिम्मी यादव, एस एन सोनी, नायब तहसीलदार हिमांशु कारपेंटर, आशीष पालवड़िया, परियोजना अधिकारी अरुण शर्मा, एडीपीसी गिरीश तिवारी, एटीओ एलएन मकवाना, उपयंत्री एसके पांडे, देवेंद्र परमार को नियुक्त किया गया है। अधिकारियों को मंदिर का भ्रमण कराकर मंदिर की व्यवस्था के बारे में बताया गया। अब जल्द ही सभी अधिकारी मंदिर की व्यवस्था संभालेंगे। कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि महाकाल लोक बनने के बाद भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य शासन ने आईपीएस को प्रशासक बनाया है। अब दो डिप्टी कलेक्टर सहित नायब तहसीलदार और नए अधिकारी मंदिर में इंजीनियरिंग विंग, सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्था संभालेंगे।

112 इंडिया एप से भी मिलेंगी डायल-100 सहित अन्य आपातकालीन सेवाएं

सच प्रतिनिधि II भोपाल।

प्रदेश के लोगों को अब पुलिस व अन्य विभागों से जुड़ी वे सभी आपातकालीन सुविधाएं मिल सकेंगी, जो '112 इंडिया' एप में उपलब्ध हैं। उदाहरण के रूप में एप के माध्यम से कोई व्यक्ति पैनिक बटन को क्लिक करता है, तो इसकी सूचना उस क्षेत्र के 112 कंट्रोल रूम में मिल जाएगी। पुलिस मुख्यालय इस एप को डायल-100 के साथ एकीकृत करने जा रहा है। इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है। अभी हेल्पलाइन नंबर 112 पर कोई काल करता है, तो प्रदेश में डायल-100 के कंट्रोल रूम से कॉल जुड़ जाती है, पर इस एप के माध्यम से सुविधा नहीं मिल पा रही थी।

एप में आमजन की सुरक्षा से जुड़े 12 तरह के फीचर हैं। चिकित्सा और आपातकालीन सेवाएं, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी सुविधाएं इस एप से प्राप्त की जा सकती हैं। इसमें आपातकालीन सेवा प्राप्त करने के लिए फोटो और वीडियो अपलोड करने की सुविधा भी है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों को एकीकृत कर 112 से जोड़ दिया है। एप से भी सभी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। रेडियो दूरसंचार मुख्यालय ने एप को डायल-100 सेवा से एकीकृत करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। एजेंसी चयन होने में लगभग दो माह लगेंगे। इसके बाद एक माह दोनों सेवाओं को एकीकृत करने में लगेंगे। बता दें कि कॉल करने की तुलना में एप में ज्यादा सुविधाएं हैं। सबसे बड़ा लाभ यह कि सहायता मांगने वाले की लोकेशन भी एप के माध्यम से नियंत्रण कक्ष तक पहुंच जाती है। इसी तरह ट्रेन में यात्रा करते समय कोई समस्या आती है, तो उसके लिए भी एप के माध्यम से सहायता ली जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि सहायता के लिए 100 या 112 नंबर डायल करने सबसे पहले सूचना डायल-100 के नियंत्रण कक्ष में आती है। इसके बाद उस कॉल को संबंधित काल सेंटर से जोड़ा जाता है, जैसे रेलवे में सुरक्षा संबंधी सहायता मांगने पर उसे आरपीएफ व जीआरपी के कंट्रोल रूम से तत्काल जोड़ दिया जाता है।